दैनिक

# न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 17 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 287

## यूरोप में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले : पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल , ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर बढ़ना चिंता का विषय है, यूरोप के कई देशों में केस बढ़ रहे हैं यह हमारे लिए चिंता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कोरोना रहने से नए वैरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमें इससे बचवा करना होगा। हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं ऐसे में सतर्कता बरतनी होगी। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रित नहीं हई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसके लिए हमें अभी से माइक्रो कंटेमेंट जोन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने इस संकट के वक्त में एक-दूसरे से सीखने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरी लहर के दौरान कुछ राज्यों ने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेंमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान दिया। उसी कारण वह हालात को संभालने में कामयाब हुए।

**पीएम मोदी ने दिया 4टी का मंत्र-** पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के करीब 80 फीसदी मामले इन्हीं 6 राज्यों ( आज मीटिंग में शामिल ) से हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल में बढ़ते मामले चिंताजनक है, क्योंकि ये सब दूसरी लहर के पहले वाले लक्षण हैं। हमें एक बार फिर टेस्ट, ट्रैक और टीका के रणनीति पर आगे बढ़ना होगा । पीएम मोदी ने कहा कि जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीनेशन काफी महत्वपूर्ण है। टेस्टिंग में सबसे अधिक त्रञ्ज-क्ष्त्र तकनीक पर जोर देने की जरूरत है । सभी राज्यों में आईसीयू बेड्स, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए फंड आवंटन किया जा रहा है। केंद्र ने 23 हजार करोड़ का फंड दिया है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को मिशन मोड के तहत पूरा करना चाहिए।

यूरोप में बढ़ रहे कोरोना के मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। पिछले दो हफ्तों में यूरोप के देशों में कोरोना बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी केस बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए चेतावनी है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ने पर भी पीएम ने चिंता जताई और इसे रोकने की अपील की।

इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा, ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी इस बैठक में उपस्थित थे। मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने पहाड़ों और बाजारों में भीड़ बढ़ने और कोरोना नियमों का पालन नहीं करने को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने माइक्रो-कंटेनमेंट जोन पर भी जोर देने की बात कही थी।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले एके एंटनी और शरद पवार

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की। कांग्रेस नेता एके एंटनी और एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) प्रमुख शरद पवार के साथ हुई इस बैठक में दोनों को सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) जनरल बिपिन रावत व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन सीमा पर चल रहे विवाद के बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों को चीन के साथ विवाद की स्थिति को लेकर कुछ संशय थे जिनका सीडीएस और सेना प्रमुख ने समाधान किया।

### कोरोना की दूसरी लहर में रिहा कैदी अगले आदेश तक नहीं करेंगे आत्मसमर्पण : सुप्रीम कोर्ट

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि उसके निर्देश पर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा रिहा किए गए कैदियों को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों को निर्देश दिया कि जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों की रिहाई पर उसके सात मई के आदेश को लागू करने में अपनाए गए नियमों की जानकारी पांच दिन के भीतर दाखिल की जाए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) से राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पालन किए गए नियमों के विवरण मिलने के बाद एक रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। कोविड-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि का संज्ञान लेते हुए, पीठ ने सात मई को उन सभी कैदियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था जिन्हें पिछले साल जमानत या पेरोल दी गई थी।

### गोवा के मुख्यमंत्री का फेसबुक अकाउंट हैक, शिकायत दर्ज

**पणजी (आरएनएस)।** गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का पुराना फेसबुक अकाउंट हैक होने से एक दिन पहले हैकर्स ने एक सोशल मीडिया यूजर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पेमेंट मोड के जरिए पैसे भेजने को कहा है। सावंत ने कहा कि इस मामले में एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन हैकर्स द्वारा लक्षित व्यक्ति, प्रमेश असोलकर ने कहा कि वह अभी भी सदमे में है कि राज्य के मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को टैप किया गया था। हैकर ने खुद को सावंत बताया और असोलकर से तुरंत 30,000 रुपये भेजने का अनुरोध किया जो दो घंटे में वापस कर दिए जाएंगे। असोलकर ने कहा, गुरुवार रात करीब 9.30 बजे, मुझे प्रमोद सावंत से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट की सूचना मिली। प्रोफाइल में गोवा के मुख्यमंत्री की फोटो और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कमल का चिन्ह था। मुझे यकीन था कि यह वास्तविक था। जब हैकर ने उनसे पैसे मांगे तो असोलकर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। असोलकर ने कहा, लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहने की जरूरत है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री का अकाउंट ही हैक हो गया हो। मुख्यमंत्री ने अपने पुराने फेसबुक अकाउंट के हैक होने की भी पुष्टि की। सावंत ने कहा, मेरा पुराना फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। मैंने शिकायत दर्ज कराई है।

### प्रियंका पहुंची लखनऊ, कानून व्यवस्था को लेकर मौन धरने पर बैठीं

**लखनऊ (आरएनएस)।** यूपी में मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक में दलों ने अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन धरने पर बैठी हैं। चुनाव को लेकर रणनीति बनाने और उस पर चर्चा के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई हैं। अगले तीन दिनों तक वह यहां कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगी। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचीं। जहां उन्होंने राष्ट्रपिता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने यहां प्रदेश में फैले जंगलराज, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ दो मिनट का मौन भी रखा।

## यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा हलफनामा

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** कोविड काल में कांवड़ यात्रा निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान जस्टिस नरिमन ने कहा कि राज्य सरकार सौ फीसदी क्षमता के साथ कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकती है। इस पर सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार सिर्फ प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा निकालेगी। तमाम दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पुनर्विचार करके हलफनामा मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार की पुनर्विचार के कहा। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उसने प्रतीकात्मक रूप से यात्रा को इजाजत दी है। हालांकि इस मामले में हलफनामा दायर करने के बाद कोर्ट 21 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन ने कहा कि यूपी ने फैसला किया कि पूर्ण प्रतिबंध अनुचित होगा, इसलिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रतीकात्मक तरीके से कांवड़ यात्रा निकालने पर विचार किया है। कांवड़ को गंगाजल टैंकरों में उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा कांवड़ निकालने की अनुमति लेनी होगी। आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या पूरी तरह से वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को ही इसमें शामिल होने की इजाजत होगी।

## अब तक राज्यों कोरोना वैक्सीन टीके की 41.10 करोड़ से अधिक खुराक दी गयी : केंद्र

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 41.10 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं और राज्यों के पास तथा निजी अस्पतालों में 2.51 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं।

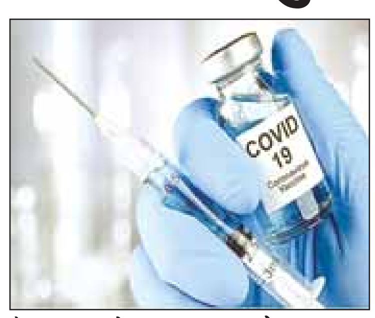


मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टीके की 52,90,640 और खुराकों की आपूर्ति की जा रही है। बयान में कहा गया कि सभी स्रोतों के माध्यम से अब तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 41.10 करोड़ (41,10,38,530) से अधिक खुराक प्रदान की जा चुकी हैं और आगे 52,90,640 खुराकें आपूर्ति करने की प्रक्रिया चल रही है। सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बर्बाद हो चुकी खुराकों समेत कुल 38,58,75,958 खुराक की खपत हुई है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी 2,51,62,572 खुराकें उपलब्ध हैं। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम नया चरण 21 जून को शुरू हुआ और इसके तहत केंद्र सरकार सभी वयस्कों का निशुल्क टीकाकरण कर रहा है। पहले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके मुफ्त थे। टीकाकरण अभियान के नए चरण में केंद्र सरकार देश में टीका निर्माताओं द्वारा तैयार किए जा रहे 75 प्रतिशत टीकों की खरीद कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इनकी निशुल्क आपूर्ति कर रही है।

## देश में तीन दिन बाद फिर कम हुआ कोरोना का आंकड़ा

### » 24 घंटे में 38,949 नए मामले, 542 लोगों की मौत

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** देश में नए कोरोना मरीजों और संक्रमण से मौतों का आंकड़ा शुक्रवार को कम हुआ है। पिछले चौबीस घंटो में देश में कोरोना के 38,949 नए मामले और 542 और लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इस प्रकार में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,10,26,829 हो गई। जबकि संक्रमण से मौतों की संख्या बढ़कर 4,12,531 हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकडो के अनुसार देश में देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,30,422 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.39 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 1,619 कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.28 प्रतिशत है। मंत्रालय ने गुरुवार को ताजा आंकड़े जारी कर बताया था कि बीते चौबीस घंटों में देश में 41,806 नए मामले आए जबकि 581 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन पहले 39,130 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए थे जबकि 4,32,041 मरीज विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती थे।

आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 44,00,23,239, नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 19,55,910 नमूनों की जांच गुरुवार को की गई। देश में नमूनों में संक्रमण की पुष्टि की दैनिक दर 1.99 प्रतिशत है। यह पिछले 25 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम है। नमूनों में संक्रमण की पुष्टि की साप्ताहिक दर 2.14 प्रतिशत है। अभी तक कुल 3,01,83,876 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.33 प्रतिशत है। देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 39.53 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

## हाईकोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

### » कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना नीतिगत मामला

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को दरकिनार कर दिया है जिसमें नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) द्वारा सितंबर 2012 में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने के निर्णय को सितंबर 2002 से लागू करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने नोएडा द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण किया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढाई जानी चाहिए या नहीं, यह नीतिगत मामला है। अगर सेवानिवृत्ति की आयु बढाने का निर्णय लिया गया है तो यह बढ़ोतरी किस तारीख से होनी चाहिए, यह नीतिगत होता है। ऐसे में हाईकोर्ट को इस मसले में दखल नहीं देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने नोएडा के कुछ कमर्चारियों द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना फैसला दिया था। रिट याचिका दायर करने वाले कर्मचारी इस बात से खफा थे कि सेवानिवृत्ति की आयु बढाने के निर्णय को अधिसूचना वाली तारीख से लागू किया गया था।

## मोदी ने किया गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया स्टेशन

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो अपग्रेडेड है और जहां पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा ही अनुभव होने वाला है। भारतीय रेलवे इस तरह के देश में करीब सात अपग्रेडेड रेलवे स्टेशन बनाने जा रही है।

रेलवे बोर्ड के चैयरमेन सुनीत शर्मा के अनुसार गुजरात गांधीनगर रेलवे स्टेशन के अलावा भोपाल के हबीबगंज और बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया के स्टेशन का काम अंतिम चरणों में है। जल्द ही दोनों स्टेशन भी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के बिजवासन और सफदरजंग स्टेशन, लखनऊ स्थित गोमतीनगर और धार्मिक नगरी अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायाकल्प काम भी जोरों पर है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नई सुरक्षा तकनीक के साथ फायर सेफ्टी, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, स्कैनिंग मशीन, आधुनिक साइनेज और सूचना डिस्प्ले लगाए गए हैं। स्टेशन का निर्माण अगले 50 साल को देखते हुए किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को पर्यावरण के अनुकूल निर्माण के साथ हरित भवन मापदंडों के अनुसार बनाया गया है। इसकी बिजली की मांग का लगभग 70 फीसदी सौर ऊर्जा के उपयोग से पूरा किया जाएगा। रेलवे स्टेशन की कुल बिजली की मांग 950 किलोवाट है, और रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर पर लगाए गए फोटोवोल्टिक सेल 660 किलोवाट तक की बिजली उत्पादित कर सकते हैं।

### अयोध्या स्टेशन का लुक मंदिर जैसा होगा

राम मंदिर के साथ अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी जल्द ही भव्य रूप में नजर आएगा। इस स्टेशन का लुक मंदिर जैसा होगा और स्टेशन के मुख्य द्वार पर स्टेनलेस स्टील का फाटक लगाया जाएगा। रिडेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेशन का कायाकल्प करने में रेलवे को करीब तीन साल का समय लगेगा। 104 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन किया जाएगा, इसमें बजट में 18.16 करोड़ रुपये पहली किश्त के रूप में आवंटित किए गए हैं। इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज, फ्री वाईफाई, वेटिंग लाउंज, प्लैटफॉर्मों पर वाटर वेंडिंग मशीन, वाटर कूलर, सर्कुलेटिंग एरिया में शौचालय, फूडकोर्ट सहित तमाम सुविधाएं दी जाएंगी।

### 90 स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी

पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 90 रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। रेलवे बोर्ड चाहता है कि इन स्टेशनों पर सिक्योरिटी इन्फ्रा को मजबूत किया जाए। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों की तरफ से संचालन किए जा रहे एयरपोर्ट के मॉडल पर विचार किया जा रहा है।बाद दर्ज हुए हैं।